सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

कानपुर, गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 329, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

इनसाइड पत्नी ने ओयो होटल में प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा... » Pg06

» Pg12

लोकतंत्र की शुचिता के लिए एसआईआर जरूरीः ब्रजेश पाठक

गोवा से भागकर थाईलैंड के फुकेट में छुपे थे दोनों

100 घंटे के अंदर दबोचे गए भगोड़े लूथरा ब्रदर्स

दोनों हाथों में हथकड़ी, पासपोर्ट पर कैंसिलेशन का लाल निशान, चेहरे पर शिकन, अब जल्दी लाए जाएंगे भारत

नाईट क्लब अग्निकांड

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया।

गोवा। गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके अनुसार नाइटक्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। इन दोनों को भारत वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही दोनों को भारत लाकर यहां उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही गोवा पुलिस द्वारा इन दोनों भाईयों के पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिए गए हैं।

यह मामला 6 दिसंबर को गोवा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नामक एक नाइट क्लब में आग लगने से जुड़ा है। इस दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। सौरभ और गौरव लूथरा नामक यह दो भाई इस क्लब के मुख्य मालिक है। दुर्घटना की खबर सामने आने के तुरंत बाद ही यह दोनों भाई देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे। जांच के अनुसार, जब नाइट क्लब में आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंची उसी वक्त लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड की टिकट बुक की थी।

थाइलैंड पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद इसी होटल में दोनों भाइयों को रखा है। उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन में भयानक हादसे के कुछ ही घंटों बाद दोनों फुकेट रवाना हो गए। उन पर गैर इरादतन हत्या के आरोप हैं।

ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंपा गया अजय गुप्ता

उधर, अग्निकांड के मामले में नाइटक्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया है। अजय गुप्ता को घटना की जांच के सिलसिले में दिल्ली में हिरासत में लिया गया था। गोवा पुलिस ने उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के सामने पेश किया और ट्रांजिट रिमांड की मांग की। कोर्ट ने इंडिगो परिचालन संकट को देखते हुए 36 घंटे की रिमांड मंजूर की। जज ने निर्देश दिया कि अजय गुप्ता की रीढ़ की हड्डी की चोट और अन्य मेडिकल समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाए और समय पर दवाएं दी जाएं।

» छह दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में लगी थी आग।

आग लगते ही टिकट बुक करके थाईलैंड भागे दोनों भाई

दोनों भाइयों ने 6-7 दिसंबर की रात 1:17 बजे ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट पर लॉग इन करके टिकट बुक की और सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली से फुकेट पहुंच गए। लूथरा ब्रदर्स के साथ साथ उनके अन्य पार्टनर, क्लब का मैनेजर और कई कर्मचारी दिल्ली के रहने वाले हैं इसलिए ही दिल्ली पुलिस भी गोवा पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में बुधवार को दिल्ली से क्लब के चार मालिकों में से एक को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, गोवा पुलिस ने अग्निकांड के मामले में पांच प्रबंधकों और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार किया। आग लगने की घटना रात को हुई और जल्दी ही इसने पूरे स्थल को अपने लपेटे में ले लिया। भारत के अधिकारी अब थाईलैंड के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, ताकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

बुधवार को क्लब का एक पार्टनर हुआ था गिरफ्तार

अजय गुप्ता नामक यह आरोपी मूल रूप से जम्मू का रहने वाला है। गोवा पुलिस अजय को बुधवार रात ही गोवा लेकर आ गई थी। अजय से जब मीडिया ने इस घटना के बारे में सवाल किया तो उसने कहा कि मैं सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर हूं, मुझे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस के अनुसार, अजय की गोवा के क्लब में बड़ी हिस्सेदारी थी। गुप्ता के अलावा, इस मामले में अभी तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भरत कोहली शामिल है।

दिल्ली कोर्ट ने याचिका खारिज की

बुधवार को ही लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि वह काम के सिलसिले में थाईलैंड गए थे और अब भारत आना चाहते हैं, लेकिन यहां आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में अदालत उन्हें 4 हफ़्तों की ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत दे ताकि उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। कहा गया था कि मामले की जांच तक उन्हें पुलिस हिरासत में भी न लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें सुरक्षा देने से मना कर दिया था। दोनों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है और उनका भारत प्रत्यर्पण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने क्या कहा?

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस त्रासदी की जांच रिपोर्ट आठ दिन के भीतर तैयार हो जाएगी। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है और सभी मनोरंजन स्थलों में सुरक्षा ऑडिट सख्त कर दिया है। उन्होंने कहा, सरकार ने तीन लोगों को निलंबित किया है। हमने मजिस्ट्रेट जांच शुरू की है। जांच रिपोर्ट आठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। ऑडिट कराने के लिए हमने राजस्व सचिव के तहत एक ऑडिट समिति बनाई है। वे यहां विभिन्न प्रकार के क्लबों का ऑडिट करेंगे।

अग्निकांड के बाद उत्तरी गोवा जिला प्रशासन ने नाइट क्लबों, होटलों और अन्य पर्यटक प्रतिष्ठानों के अंदर अतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कांग्रेस में दिल्ली महारैली की तैयारियाँ तेज

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। आगामी 14 दिसम्बर को दिल्ली में प्रस्तावित वोट चोर गद्दी छोड़ महा रैली को सफल बनाने के लिए कॉग्रेस ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं। बुधवार को अखिल भारतीय कॉग्रेस समिति के राष्ट्रीय सचिव नीलान्शु चतुर्वेदी ने कानपुर नगर ग्रामीण कॉग्रेस समिति की बैठक लेकर तैयारियों और संगठन सृजन कार्यक्रम की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया।

कॉग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीलान्शु चतुर्वेदी ने कानपुर पहुंचकर ली संगठन की बैठक, पदाधिकारियों को दिए लक्ष्य

महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों और समन्वयकों को रैली में पहुँचने का स्पष्ट लक्ष्य देते हुए कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। चतुर्वेदी ने बताया कि केवल उत्तर प्रदेश से ही लगभग दो लाख कार्यकर्ता दिल्ली पहुँचेंगे, जिनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि कानपुर नगर और देहात से भी हजारों की संख्या में कॉग्रेसजन रैली में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय सचिव ने एस.आई.आर. प्रक्रिया तथा बी.एल.ए.–2 की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद घबराहट में सरकार ने यह प्रक्रिया लागू की है, जो पूर्णतः दोषपूर्ण है। उन्होंने संगठन को और अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए।

जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने जानकारी दी कि नगर ग्रामीण कॉग्रेस ने लगभग सभी बी.एल.ए.–2 सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दी है तथा संगठन सृजन का कार्य अंतिम चरण में है। अब पूरा ध्यान दिल्ली की महा रैली की सफलता पर केंद्रित किया जा रहा है।

बैठक में समन्वयक विजय मिश्र ने कार्यकर्ताओं से वाहनों तथा रेल के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुँचकर रैली को अभूतपूर्व बनाने का आह्वान किया।

बैठक में वरिष्ठ नेता महेन्द्र भदौरिया, उमेश दीक्षित, आनन्द वर्मा, राजू कश्यप, शिवनाथ शुक्ला, दिनेश शुक्ला, प्रतिभा अटल पाल, मानेस दीक्षित, ममता तिवारी, पार्षद नूरैन अहमद टारजन, सतीश दीक्षित, बाबूराम सोनकर, धर्मराज चौहान, अमिताभ भदौरिया, शक्ति पाण्डेय, राजीव द्विवेदी, अंकित कन्नौजिया, अनिल पाण्डेय, देवी प्रसाद निषाद, विजय निषाद, मनजीत सिंह खालसा, तिलक चन्द्र कुरील सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सीएम पोर्टल पर कानपुर जोन प्रदेश में बना फिर नंबर वन

» शिकायतों के निस्तारण में एडीजी आलोक सिंह की मॉनिटरिंग का दिखा असर,प्रदेश में फिर बजा डंका

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित जनसुनवाई समाधान(आईजीआरएस)पर प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण,त्वरित और समयबद्ध निस्तारण पर शासन की तरफ से जारी रैंकिंग में नवम्बर महीने में कानपुर जोन का दबदबा एक बार फिर कायम रहा।इस बार भी कानपुर जोन प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया है।जिसके साथ ही तेजतर्रार एडीजी आलोक सिंह के कुशल नेतृत्व में कानपुर ज़ोन की कार्यशैली को एक बार फिर मजबूती से सराहा जा रहा है।इसी क्रम में बता दे कि कानपुर ज़ोन के अंतर्गत आने वाले कानपुर रेंज और झांसी रेंज के साथ फतेहगढ़,कन्नौज तथा जोन के कुल 75 थानों को भी जनसुनवाई समाधान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त किया है। एडीजी आलोक सिंह द्वारा ज़ोन अंतर्गत आने वाले सभी आठों जनपदों के प्रभारियों को जनसुनवाई समाधान (आईजीआरएस) पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों का उच्चकोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने एवं जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से प्रदेश सरकार के मंशानुरूप पूर्ण मनोयोग से उनकी समस्याओं के विधिक निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है जिससे आमजनमानस में पुलिस की उत्कृष्ट छवि,निष्पक्ष कार्यप्रणाली एवं विश्वसनीयता की भावना बरकरार रहे।वहीं एडीजी ने बताया कि जिन थानों या जनपदों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है,उनके कार्यों की विशेष समीक्षा की जाएगी ताकि शिकायत निस्तारण प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके।

व्यापारी से वसूली का आरोप, खाद्य निरीक्षक निलंबित

» व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी व सबूतों के बाद हुई कार्रवाई

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक अनिल पाल को व्यापारी से जबरन वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। व्यापारी राजेश गुप्ता के अनुसार, निरीक्षक ने दुकान की जांच के नाम पर 10,500 रुपए वसूले। यह कार्रवाई एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के आदेश पर की गई है।

शिकायत के अनुसार, 4 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल पाल दुकान पर पहुंचे और नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर भारी जुर्माने की धमकी दी। व्यापारी का आरोप है कि निरीक्षक अपने साथ एक निजी व्यक्ति को भी लाए थे, जिसने दुकान में धूम्रपान करते हुए दबाव बनाया।व्यापारी ने बताया कि भयवश उसे 6,000 रुपए नकद, 4,000 रुपए ऑनलाइन और 500 रुपए चालक को देने पड़े। पैसा अंशुल सिंह के खाते में ट्रांसफर कराया गया था।शिकायत के साथ भेजे गए सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर मामले की जांच सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय संजय प्रताप सिंह को सौंपी गई।

जांच रिपोर्ट के बाद गुरुवार रात निरीक्षक अनिल पाल को निलंबित कर लखनऊ मंडलीय कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। उनके खिलाफ आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी तय की गई है।इधर व्यापारी राजेश गुप्ता की तहरीर पर महाराजपुर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

'कथित पत्रकार' बनकर घूम रहे हेडमास्टर जितेंद्र कमल निलंबित

वह कई दिनों से स्कूल से गायब चल रहे थे, जांच में खुली पोल

» बीएसए ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है

» निलंबित कर रसूलाबाद के रायपुर प्राथमिक विद्यालय स्कूल में संबद्ध किया गया

FOLLOW UP

» स्वराज इंडिया ब्यूरो चीफ

कानपुर देहात। जिले के रसूलाबाद ब्लाक क्षेत्र के मेघजाल गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ़ जितेंद्र कमल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी स्कूल में गणित-विज्ञान शिक्षक के रूप में 11 फ़रवरी 2009 को नियुक्त हुए जितेंद्र कमल लंबे समय से नियमित वेतन तो ले रहे थे,

लेकिन विद्यालय में उनकी उपस्थिति बेहद संदेहास्पद पाई गई।इस बीच उन्होंने सरकारी नौकरी को दरकिनार कर 'कबीर न्यूज' नाम से यूट्यूब चैनल बनाकर कानपुर महानगर में कथित पत्रकारिता शुरू कर दी। विभिन्न सरकारी विभागों और योजनाओं पर समीक्षा करने लगे, तथा कई जनप्रतिनिधियों पर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करते हुए वीडियो पोस्ट करने लगे। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, मामला चर्चा में आ गया। स्कूल में उनकी अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठे तो बीएसए अजय कुमार मिश्रा के निर्देश पर बीईओ अजब सिंह ने मौके पर जाकर जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि प्रधानाध्यापक कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। विद्यालय की एक महिला शिक्षिका ने भी बताया कि वह कभी-कभार ही स्कूल आते हैं।बीएसए ने बताया कि अनुपस्थिति के आधार पर प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है। आगे की विभागीय विधिक कार्रवाई जारी रहेगी।सरकारी स्कूल के हेड मास्टर का इस तरह नौकरी छोड़कर यूट्यूबर बन जाना शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। विभाग अब इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रहा है।

स्वराज इंडिया में प्रकाशित हुई थी खबर

देश की रक्षा करने वाले फौजी, अब अपने ही घर के लिए लड़ने को मजबूर

नबीपुर में रिटायर फौजी भाइयों का निर्माण कार्य रोकने पर विवाद तेज, स्थानीय लोगों पर वसूली के आरोप

» स्वराज इंडिया ब्यूरो चीफ

कानपुर देहात। सीमा पर दुश्मनों से मुकाबला करने वाले जवान जब रिटायर होने के बाद अपने लिए एक छोटा-सा घर बनाने लगें और उन्हें वहीं रोक दिया जाए, तो यह किसी भी सैनिक के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। कानपुर देहात में दो रिटायर फौजी भाइयों को इसी दर्द से गुजरना पड़ रहा है। भारी मन से दोनों ने अपनी आपबीती मीडिया के सामने रखी।

मामला अकबरपुर तहसील के नबीपुरङ्कठगांव रोड का है। तुर्की मऊ गांव के निवासी रिटायर फौजी कैप्टन दिनेश बाबू सिंह और उनके भाई जगमोहन सिंह ने फौज में तैनाती के दौरान वर्ष 2006 में नबीपुर में जमीन खरीदी थी, ताकि रिटायरमेंट के बाद परिवार संग शांतिपूर्ण जीवन बिता सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का निर्माण शुरू कराया, क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया।फौजी भाइयों का आरोप है कि निर्माण रुकवाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यहां तक कि फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकियां भी दी गईं। मंगलवार को महेश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ एससी-एसटी आयोग के सदस्य रमेश चन्द्र कुंड से सर्किट हाउस में मिलकर संदिग्ध वस्तु खाने का दावा कर माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की। बाद में दोनों को अस्पताल भेजना पड़ा। पीड़ित फौजी भाइयों का कहना है कि यह पूरा विवाद उनसे वसूली की नीयत से खड़ा किया गया है। परेशान होकर उन्होंने तहसील प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। प्रशासन ने जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए हैं। कैप्टन दिनेश बाबू सिंह ने बताया कि प्रशासन उनकी बात सुन रहा है और सहयोग कर रहा है, नहीं तो क्षेत्रीय लोग उन्हें बेहद परेशान कर रहे हैं।

केआईटी कॉलेज के छात्रों में आक्रोश, परीक्षा केंद्र बदलने के खिलाफ प्रदर्शन, अवैध वसूली का भी आरोप

» स्वराज इंडिया ब्यूरो चीफ

कानपुर। केआईटी कॉलेज में छात्रों ने परीक्षा केंद्र को अंतिम समय में बदलने और अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलेज डायरेक्टर ने परीक्षा प्रक्रिया को यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अनुरूप बताया है।

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा स्थित केआईटी कॉलेज में गुरुवार को एमबीए और बीटेक के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कैंपस के अंदर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने पूरे सत्र में यही बताया कि परीक्षाएं कॉलेज कैंपस में ही कराई जाएंगी। अब जब परीक्षा में मात्र दस दिन बचे हैं, तो अचानक सूचना दी गई कि परीक्षाएं यूनिवर्सिटी में होंगी। छात्रों का कहना है कि कम समय में नई जगह पर परीक्षा देने की तैयारी करना मुश्किल होगा। आरोप यह भी लगाया गया कि कॉलेज प्रबंधन पूरे साल अलग-अलग तरीकों से अतिरिक्त पैसों की उगाही करता है।

केआईटी कॉलेज में छात्रों ने परीक्षा केंद्र को अंतिम समय में बदलने और अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलेज डायरेक्टर ने परीक्षा प्रक्रिया को यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अनुरूप बताया है।

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा स्थित केआईटी कॉलेज में गुरुवार को एमबीए और बीटेक के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कैंपस के अंदर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने पूरे सत्र में यही बताया कि परीक्षाएं कॉलेज कैंपस में ही कराई जाएंगी। अब जब परीक्षा में मात्र दस दिन बचे हैं, तो अचानक सूचना दी गई कि परीक्षाएं यूनिवर्सिटी में होंगी। छात्रों का कहना है कि कम समय में नई जगह पर परीक्षा देने की तैयारी करना मुश्किल होगा। आरोप यह भी लगाया गया कि कॉलेज प्रबंधन पूरे साल अलग-अलग तरीकों से अतिरिक्त पैसों की उगाही करता है। एडमिट कार्ड होने के बावजूद पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और परीक्षा के समय भी अवैध वसूली की जाती है। छात्रों ने बताया कि कई बच्चे दूरदराज के जिलों से यहां पढ़ने आते हैं।

योगी-मोदी पर अपशब्द कहने वाले नशेड़ी अरेस्ट

एक मिनट 32 सेकंड के वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप, बियर की कैन ओपन करते ही युवकों का हाई वोल्टेज ड्रामा

विधायक, एसडीएम, एसीपी, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज तक सभी पर कीं अभद्र टिप्पणियां...!

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। ककवन थाना क्षेत्र के रहीमपुर बिषधन गांव में कुछ युवकों का शराब के नशे में किया गया हाई वोल्टेज ड्रामा मंगलवार को पुलिस कार्रवाई में बदल गया, जब उनका एक मिनट 32 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में युवक बियर की केन खोलते ही न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द बोलते दिखे, बल्कि स्थानीय विधायक, एसडीएम, एसीपी, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज तक पर भी अभद्र टिप्पणियों की झड़ी लगा दी। और ठेके के कर्मचारियों से गाली गलौज की।

उधर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बार प्रशासन हरकत में आया। एसीपी मंजय सिंह के आदेश पर ककवन पुलिस ने वायरल वीडियो की छानबीन की। पुलिस ने दोनों की पहचान रहीमपुर बिषधन गांव के आमिर और अभिषेक सोनी के रूप में की और उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपका अपना स्वराज इंडिया अख़बार वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ अपशब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। घटना के बाद बिषधन और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का माहौल है।

अंडरपास के पास फेरीवाले से लूट

नकाबपोश बदमाशों की तलाश तेज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

शिवराजपुर/बिल्हौर (कानपुर)। जीटी रोड स्थित अंडरपास के पास सोमवार रात फेरी लगाकर लौट रहे ई-रिक्शा चालक को चार नकाबपोश बदमाशों ने लूट लिया। मारपीट कर नकदी और परचून का सामान लूट लिए जाने के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है।

उत्तरीपूरा निवासी रविकांत शुक्ला रोजाना ई-रिक्शा से गांव-गांव परचून का सामान सप्लाई करते हैं। सोमवार देर रात जब वह शिवराजपुर स्थिर दरिया नेवादा टोल प्लाजा की ओर से घर लौट रहे थे, तभी अंडरपास के पास घात लगाए बैठे करीब चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। विरोध करने पर उनकी जमकर पिटाई की गई और बदमाश रिक्शे में रखी नकदी व सामान लूटकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।

कार्यवाहक थानाध्यक्ष ने बताया कि वारदात में शामिल सभी आरोपी नकाब पहने हुए थे, जिससे पहचान में दिक्कत आ रही है। पुलिस टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की गतिविधियों की जांच की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सुराग मिलने पर जल्द ही लुटेरों को पकड़ा जाएगा।

प्रधानपुर में कच्चा घर खाक,आगजनी पर विवाद की चिंगारी भड़की

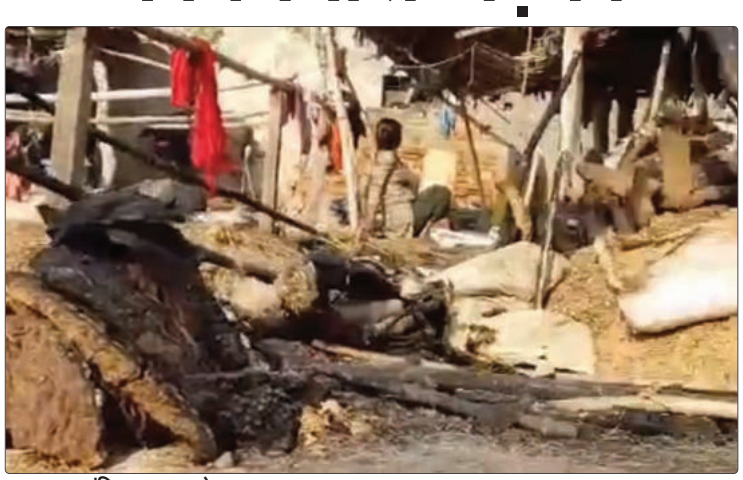

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

शिवराजपुर/बिल्हौर (कानपुर)। प्रधानपुर गांव में सोमवार देर शाम एक कच्चे घर में लगी आग ने परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया। घास-फूस और मिट्टी से बनी झोपड़ी में अचानक उठीं लपटें कुछ ही मिनटों में बेकाबू हो गईं। धुआं उठता देख ग्रामीण दौड़ पड़े और बाल्टियों व पाइपों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग तो शांत हो गई, लेकिन तब तक झोपड़ी का ढांचा मिट्टी में मिल चुका था।

आग की चपेट में आने से गोवर्धन के घर में रखा छह बोरी अनाज लाही, गेहूं और उड़द पूरी तरह जल गया। इसके साथ ही करीब 30 हजार रुपये नकद, कपड़े-बिस्तर और रोजमर्रा का अधिकांश सामान भी राख में बदल गया। अचानक हुए इस नुकसान से परिवार बदहवास है।

घटना के बाद मामला केवल आग तक सीमित नहीं रहा। पीड़ित पक्ष ने पड़ोसियों पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया है। गोवर्धन की पत्नी गुड्डी ने थाने में दी गई शिकायत में दो व्यक्तियों का नाम लेते हुए कहा कि पुरानी रंजिश के चलते उनके घर को निशाना बनाया गया।पुलिस का कहना है मामले की जाँच की जा रही है।

होमगार्ड ने वेतन लेकर लौट रहे ट्रक चालक पर हमला किया

15 हजार रुपए लूटे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर(कानपुर)। मकरंद निवादा गांव में मंगलवार रात ट्रक चालक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही होमगार्ड शिवम ने चालक अमित को रास्ते में रोककर पहले शराब पिलाई, फिर लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया और उसकी जेब में रखे 15,000 रुपये निकाल लिए।पीड़ित अमित ने बताया कि वह प्रदीप नाम के ट्रक मालिक के यहां चालक है और मंगलवार को उसे वेतन मिला था। रात करीब नौ बजे जब वह घर लौट रहा था, तभी निकुंज अस्पताल उत्तरीपूरा के पास पहले से मौजूद शिवम ने उसे रोक लिया। साथ बैठकर शराब पीने के बाद शिवम ने अचानक उस पर हमला कर दिया।

हमले में गंभीर रूप से घायल अमित को ग्रामीणों ने किसी तरह परिजनों को सूचना देकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद चौकी पूरा पुलिस ने आरोपी शिवम को पकड़कर चौकी में बैठा लिया। अमित ने आरोप लगाया कि शिवम दबंग प्रकृति का है और होमगार्ड की नौकरी का दबाव दिखाकर आए दिन लोगों से झगड़ा करता है। उसने आशंका जताई कि आरोपी आगे भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है।थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि पीड़ित को उपचार के लिए भेजा गया है।मामले की जाँच की जा रही।

लोक अदालत में निपटेंगे छोटे विवाद

चौबेपुर/बिल्हौर (कानपुर)। ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से लंबित छोटे विवादों को निपटाने के लिए चौबेपुर ब्लॉक सभागार में 16 दिसंबर को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने बुधवार को इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। ग्राम न्यायालय की श्रृंखला में होने वाली इस लोक अदालत का उद्देश्य है कि छोटे झगड़े-खासकर पड़ोसी विवाद, लेन-देन के मामूली मामले और आपसी रंजिश से जुड़ी शिकायतें एक ही मंच पर शांतिपूर्ण तरीके से निस्तारित हो सकें।अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय आपके द्वार अभियान के तहत ग्रामीणों को राहत देने के लिए यह विशेष पहल की गई है, ताकि लोगों को थाने कचहरी के चक्कर न लगाने पड़ें। थाना प्रभारी आशीष कुमार चौबे ने जानकारी दी कि गांवों में होने वाले साधारण विवादों के साथ-साथ 5 हजार रुपये तक के जुर्माने वाली श्रेणी के अपराधों का निपटारा मौके पर कराया जाएगा।

सम्पादकीय

सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

विकास के नाम पर हमने सरपट वाहन दौड़ने वाली सड़कें तो बना दी, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि यात्रा दुर्घटनाओं से निरापद कैसे रहे। यह हृदय विदारक होता है कि सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियों, ट्रकों की अराजकता तथा राजमार्ग के अवरोधों के चलते परिवार के परिवार असमय काल कवलित हो जाते हैं। तंत्र की चतुराई ये होती है कि मुआवजे और दुर्घटना की फौरी जांच की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन सड़क दुर्घटना के मूल कारणों की तह तक नहीं पहुंचा जाता है।। इस संकट की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलोदी इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से दो सप्ताह में दुर्घटना के कारणों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के ा। जिससे यात्रियों से भरा तेज गति से आता एक टेम्पो ट्रेवलर टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि इसमें चार बच्चों तथा दस महिलाओं समेत पंद्रह लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए। आमतौर पर किसी भी बड़े हादसे में शिकार हुए यात्रियों की संख्या का ही जिक्र होता है और सरकार मुआवजे की घोषणा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। अधिक से अधिक हमारे विमर्श का मुद्दा यह होता है कि दोषी कौन था? कौन सा ड्राइवर लापरवाही से वाहन चला रहा था, वह नशे में था या उसे नींद की झपकी लग गई। या फिर वाहन में तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ। जो दुर्घटना का कारण बनती हैं। एक ओर जहां सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा की गई चूक होती हैं, वहीं सड़कों के किनारे बेतरतीब बने ढाबे भी होते हैं, जहां अकसर ट्रक चालक अपने वाहन गलत ढंग से खड़े कर देते हैं। लेकिन अकसर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कारक को अनदेखा करने की वजह से भविष्य में ऐसी ही दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की आशंका बलवती होती है। यह विडंबना ही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जगह-जगह टोल संग्रह केंद्रों के जरिये टैक्स तो खूब वसूले जाते हैं, लेकिन राजमार्गों को दुर्घटनाओं से निरापद बनाने के लिये गंभीर प्रयास नहीं होते। कुकरमुत्तों की तरह सड़कों का अतिक्रमण करते ढाबों पर लगाम नहीं लगायी जाती। गंभीरता से पड़ताल नहीं होती है कि क्या सड़क निर्माण में ठेकेदार ने सभी तकनीकी मानकों का पालन किया है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जवाबदेही बनती है कि राजमार्गों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये नियमित जांच-पड़ताल की जाती रहे। ताकि निर्दोष लोगों के बेमौत मरने का सिलसिला खत्म हो सके। इन विभागों व मंत्रालयों का जिम्मा सिर्फ टोल वसूलना ही नहीं है बल्कि सड़कों को सुरक्षित बनाना भी इनकी जवाबदेही है। निश्चित रूप से सड़क के निर्माण की गुणवत्ता तथा उसे दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये उच्च सुरक्षा मानकों का क्रियान्वयन भी उतना जरूरी है। इसके अलावा सख्त कानून व निगरानी के जरिये ट्रकों को सड़क के किनारे खड़े करने पर रोक लगायी जाए। देश में सैकड़ों लोगों की मौत सड़क के किनारे गलत तरीके से खड़े ट्रक से वाहनों के टकराने से होती है, लेकिन दोषी ट्रक चालक को कड़ी सजा नहीं मिलती।

सतत जागरूकता से बचेगी जनतंत्र की गरिमा

क्षमा शर्मा

राजनेताओं को यह अहसास कराया ही जाना चाहिए कि जनता को अपनी मुट्ठी में समझने की उनकी प्रवृत्ति देश के जागरूक मतदाता को स्वीकार नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों- मर्यादाओं का तकाज़ा है कि नेता अपनी सीमाएं समझें और जनता अपनी...राजनेताओं को यह अहसास कराया ही जाना चाहिए कि जनता को अपनी मुट्ठी में समझने की उनकी प्रवृत्ति देश के जागरूक मतदाता को स्वीकार नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों- मर्यादाओं का तकाज़ा है कि नेता अपनी सीमाएं समझें और जनता अपनी शक्ति को पहचाने।

बिहार के चुनाव परिणाम पर 'रेवड़ी' का क्या और कितना असर पड़ता है यह तो मतपत्रों की गणना के बाद ही पता चलेगा, पर यह एक खुला रहस्य है कि हमारे राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि देश का मतदाता रेवड़ियों से रिझाया जा सकता है। देखा जाये तो एक तरह से यह देश के मतदाता का अपमान ही है कि उसके बारे में ऐसी धारणा बन रही है। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति अचानक बन गयी है, अर्से से हमारे राजनीतिक दल इस रेवड़ी- संस्कृति का सहारा लेकर चुनाव जीतने का प्रयास करते रहे हैं। शुरुआती दौर में यह काम चोरी- छिपे ढंग से होता था। मतदाताओं के बीच। अब भी ऐसा होता है, पर अब और भी रास्ते अपना लिये गये हैं, मतदाताओं को 'खरीदने' के। उदाहरण के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण के नाम पर बिहार के 'सुशासन बाबू' ने राज्य की लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को दस-दस हज़ार रुपये नकद बांट दिये। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ऐसे प्रयोग हो चुके हैं।यही सब देखते हुए यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या खैरात बांटकर चुनाव जीते जा सकते हैं? भले ही कुछ राजनीतिक-विश्लेषक यह कहते रहें कि ऐसा नहीं हो सकता, पर इस धारणा से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे राजनेता यही मानते हैं कि खैरात काम आती है। अब तो हमारे सत्ताशीर्ष भी यह मान चुके लगते हैं कि चुनाव के अवसर पर रेवड़ियां बांटना ग़लत नहीं है! बात सिर्फ रेवड़ी-संस्कृति तक सीमित नहीं है। चुनाव जीतने के लिए जिस तरह जाति और धर्म का सहारा लिया जा रहा है, वह एक तरह से हमारे लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाना ही है। जातियों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और धर्म की दुहाई देकर मतदाता को भ्रमित करने की कोशिशें बिहार के इस चुनाव प्रचार में लगातार हुई हैं। यहीं यह बात भी गौर करने लायक है कि चुनाव में ठोस मुद्दे उठाने के बजाय किसी 'जंगल राज' और वोटों की कथित 'चोरी' जैसी बातों का सहारा लेना राजनीतिक दलों को कहीं अधिक उपयोगी लगा है। सत्तारूढ़ पक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी उपलब्धियों को आधार बनाकर मतदाता के समक्ष वोट मांगने जायेगा। पर देखा यह गया है कि सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष की बीस साल की पुरानी सरकार के 'जंगल-राज' का डर दिखाकर वोट पाने की उम्मीद कर रहा है। तब भी यह सवाल तो उठता ही है कि आज की युवा पीढ़ी को दो दशक पुराने उस अनुभव के आधार पर कोई निर्णय लेने के लिए कैसे कहा जा सकता है? विपक्ष से यदि कोई सवाल किया जाता है तो वह यह होना चाहिए कि उसके पास शासन का बेहतर विकल्प क्या है? यह मतदाता का अपमान नहीं तो और क्या है कि बिहार की वर्तमान सरकार की दस हज़ार रुपये की 'रिश्वत' के मुकाबले में विपक्ष तीस हज़ार रुपये नकद देने का प्रलोभन दे रहा है चुनाव जनतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होते हैं। रेवड़ियों, रिश्वत और घिसे-पिटे आरोपों के सहारे चुनाव जीतने की कल्पना ही इस उत्सव की गरिमा, महत्ता और पवित्रता को नष्ट कर देती है। यह सचमुच हैरानी की बात है कि नीतियों और नीयत के बजाय समाज को बांटने वाले नारों को चुनाव जीतने का आधार बनाया जाता है।

विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच संतुलन जरूरी

सूखते भूमिगत जल

ज्वाला सिंह दास

रिपोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं उनमें राज्य जलवायु लचीलापन कोष, हर जिले में जलवायु जोखिम मानचित्रण, हरित उद्योगों और कृषि-वानिकी को बढ़ावा तथा डिजिटल तकनीक द्वारा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली हैं। भारत की विकास यात्रा आज दो विरोधी धाराओं के बीच खड़ी है-एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण में प्रगति और दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विनाशकारी असुरक्षा। केरल, तमिलनाडु, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, जो मानव विकास सूचकांक में देश का नेतृत्व करते हैं, अब इस द्वंद्व के केंद्र में हैं। ऐसे समय में, हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ तैयार किया गया है, पूरे भारत के लिए एक दिशासूचक दस्तावेज़ के रूप में उभरकर सामने आई है।

यह ऐसी पहली रिपोर्ट है, जिसमें मानव विकास को जलवायु जोखिमों के साथ जोड़ा गया है। हिमाचल ने का मानव विकास सूचकांक 0.78 है, जो राष्ट्रीय औसत 0.63 से अधिक है, लेकिन अब जलवायु संकट इस प्रगति के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, जो न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। हिमाचल का अनुभव अकेला नहीं है। केरल का सामाजिक मॉडल बाढ़ और तटीय क्षरण से जूझ रहा है। तमिलनाडु के औद्योगिक नगरों पर जलसंकट और प्रदूषण का दबाव है। ओडिशा और गुजरात राज्यों को चक्रवातों और हीटवेव से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड और सिक्किम पर्यटन, जलविद्युत और पर्यावरण संतुलन के बीच झूल रहे हैं। रिपोर्ट में, हिमाचल की बुजुर्ग होती आबादी, युवाओं का पलायन, जल संकट और आपदाएं—को चिन्हित किया गया है। देश-भर में बुजुर्गों का प्रतिशत 2050 तक 20 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जिससे वृद्ध स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा का दबाव बढ़ेगा। खेती की घटती आय और सीमित औद्योगिकीकरण युवाओं को गांवों से शहरों की ओर धकेल रहा है। यह पलायन, हिमाचल की तरह, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रहा है। वहीं, पंजाब के सूखते भूमिगत जल, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की सूखे से जूझती जमीन, गंगा बेसिन का प्रदूषण और हिमाचल की सूखती धाराएं—सभी एक ही कहानी कहते हैं।। शहरी दबाव के चलते जहां शिमला, सोलन और मंडी जैसे शहर कचरा, ट्रैफिक और आवासीय दबाव से त्रस्त हैं, वहीं बेंगलुरु, पुणे और गुवाहाटी जैसे महानगर भी इसी असंतुलन के शिकार हैं। इसके लिए एकीकृत शहरी नियोजन और पर्यावरण-संवेदनशील निर्माण नीति की जरूरत है। पिछले पांच वर्षों में हिमाचल को आपदाओं से लगभग 46,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत है। वर्ष 2023 में भारत-भर में 2,800 से अधिक लोगों की मृत्यु और 1.4 लाख करोड़ की क्षति जलवायु-जनित घटनाओं से हुई। हिमाचल का 75,000 करोड़ रुपये का ऋण बोझ यह दर्शाता है कि छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति कितनी नाजुक है। रिपोर्ट ने ग्रीन बॉन्ड, आपदा बीमा और कार्बन क्रेडिट जैसे उपाय सुझाए हैं। गुजरात ने पहले ही हरित ऊर्जा बॉन्ड जारी किए हैं और ओडिशा ने अपने बजट में जलवायु व्यय को शामिल किया है। हिमाचल का यह दृष्टिकोण बताता है कि हर राज्य यदि अपनी वित्तीय नीति को हरित और लचीला बनाए तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन संभव है।हिमाचल की सबसे बड़ी ताकत उसका सामाजिक समावेशन है। 58 प्रतिशत पंचायत सीटें महिलाओं के पास हैं, जिससे नीतिगत निर्णयों में लैंगिक दृष्टिकोण जुड़ गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों के लिए लक्षित योजनाएं और सार्वभौमिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं इसे एक मानव-केंद्रित शासन मॉडल बनाती हैं।

(कानपुर से वायरल सनसनीखेज वीडियो)

पत्नी ने ओयो होटल में पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा

कमरे में अपने पति और प्रेमिका को साथ देखकर महिला भड़क उठी,जमकर हुआ हंगामा, स्वरूप नगर का मामला

प्रतीकात्मक फोटो

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बीते दिनों बिल्हौर में स्टेशन के शौचालय से महिला और पुरुष के आपत्तिजनक स्थिति का वीडियो वायरल हुआ था, इसकी चर्चा आग की तरह फैली हुई है। वहीं अब सिटी के स्वरूप नगर क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने ओयो होटल पहुंचा, लेकिन उसकी पत्नी को इस बात की भनक लग गई। संदेह के आधार पर पत्नी भी होटल पहुंच गई और जैसे ही उसने कमरा खुलवाया, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में अपने पति और प्रेमिका को साथ देखकर महिला भड़क उठी।

इस दौरान कमरे में मौजूद प्रेमिका पत्नी से बार-बार वीडियो न बनाने की गुहार लगाती दिखी। प्रेमिका कह रही थी मेरे जीवन में पहले से ही बहुत परेशानी चल रही है, कृपया वीडियो मत बनाइए। इस पर पत्नी ने तंज करते हुए जवाब दिया हां दिख रहा है कितनी परेशानी है, मुझे पता है कितनी समस्या चल रही है ज मेरा पति ही आपकी समस्या दूर कर रहा है ना?

पत्नी के सवालों से प्रेमिका असहज हो गई और बोली कि वैसा कुछ नहीं है जैसा सोचा जा रहा है। वहीं पत्नी पति पर भड़कते हुए कहती रही कपड़े क्यों बदल रहे हो? कपड़े मत बदलो।

घटना का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस स्तर पर अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

गोष्ठी में न्याय व्यवस्था की मजबूती पर जोर

» असमाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने प्रदेश में बढ़ते उत्पीड़न और असमाजिक गतिविधियों पर चिंता जताते हुए न्याय व्यवस्था को और सशक्त करने की आवश्यकता बताई।

अपने सम्बोधन में मो0 उस्मान अली शाह ने कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे हो चले हैं कि न्यायपालिका तथा आयोग को सीधे गंभीर मामलों का संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आमजन को उत्पीड़क ताकतों से राहत मिल सके और असमाजिक तत्वों को कड़ा जवाब मिल सके।उन्होंने कहा कि सरकार को भी जनता की जायज़ समस्याओं को पूरी गंभीरता से लेना होगा। मानवाधिकारों के प्रति जागरूक संगठनों को आगे आकर जनता की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तभी न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। गोष्ठी में सुन्दर पहलवान, महफूज आलम, मो0 सिद्दीक शाह, मंदीप सिंह, इरशाद अहमद, अंकित अग्रवाल, अर्पित सिंह, अंकित सिंह, अनीश अहमद, जसवीर सिंह, राधा जी, मुरारी लाल जी, नायाब खान सहित विभिन्न पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में मंगलकारी फैसले

» शहर में अब सभी के लिए खुलेंगे बृजेंद्र स्वरूप पार्क का मंगल भवन और बारातशाला

» मंगलभवन के लिए 11 से 51 हजार में होगी बुकिंग, मांस और मदिरा पर हलफनामा देना होगा अनिवार्य

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर ।नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में सोमवार को कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बृजेंद्र स्वरूप पार्क, बेनाझाबर स्थित मंगल भवन अब तय शुल्क और शर्तों के साथ आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बैठक में शुल्क, सिक्योरिटी मनी, बुकिंग अंतराल से लेकर मदिरा पर रोक तक सभी व्यवस्थाएं तय कर दी गईं। प्रस्ताव पास होने के बाद महापौर का सम्मान भी किया गया ।कार्यकारिणी ने मंगल भवन की बुकिंग 11 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक तय की है। इसके साथ ही जमानत राशि अलग से देनी होगी, जो कार्यक्रम के बाद वापस की जाएगी। पात्रों को हलफनामा देना होगा कि समारोह में मास या मदिरा का उपयोग नहीं किया जाएगा ।महापौर ने बताया कि शराब सेवन रोकने के लिए मंगल भवन में मशीन लगाई जा रही है। किसी भी व्यक्ति को 4 माह के अंतराल में ही दोबारा बुकिंग मिलेगी।

8 दिनों में कब्जामुक्त होंगी सभी बारातशालाएं

बैठक में जानकारी दी गई कि नगर निगम की अधिकांश बारातशाला और सामुदायिक केंद्रों पर कब्जा है। इस पर महापौर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी जोनों में 8 दिनों के भीतर कब्जे हटाकर चाबियां जमा कराई जाएं, ताकि इनके रेट भी तय कर गरीब व आमजन को सुविधा मिल सके।

नगर निगम की इस बैठक को शहर के लिए राहत भरे निर्णयों वाली बैठक माना जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़े समारोह कम खर्च में आयोजित करने में मदद मिलेगी।

मंगल भवन में श्रेणी वार फीस

अन्त्योदय राशन कार्ड व दिव्यांगजन -11,000 रुपये + 5,000 सिक्योरिटी
निगम/जलकल के चतुर्थ श्रेणी स्थायी कर्मचारी -31,000 रुपये
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक- 51,000 रुपये
सभी शुल्क में 18प्रतिशत जीएसटी शामिल
गरीबों से 11 हजार और अन्य से 20 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी ली जाएगी।

वंचित समाज के सामूहिक विवाह पर विशेष रियायत

पंजीकृत संस्था/एनओसी को वंचित समाज के सामूहिक विवाह के लिए अलग शुल्क निर्धारित किए गए–
1 से 11 जोड़ें- 11,000 रुपये
11 से 21 जोड़ें-21,000 रुपये
21 से 51 जोड़ें -51,000 रुपये

स्व. गंगूबाबा बारातशाला के भी रेट तय

फजलगंज स्थित नव निर्मित स्व. गंगूबाबा बारातशाला के शुल्क भी कार्यकारिणी ने तय कर दिए। अन्त्योदय व दिव्यांगजन- 21,000 रुपये-निगम/जलकल स्थायी कर्मचारी, पार्षद/पूर्व पार्षद, ईडब्ल्यूएस- 51,000 रुपये अन्य-71,000 रुपये

सामूहिक विवाह हेतु 21,000 से एक लाख तक शुल्क

सभी शुल्कों पर 18त्न जीएसटी लागू होगा। सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपये तय की गई।

महाठग की कुंडली खंगालने एसआईटी ले गई देहरादून, अलग नाम से तीन पासपोर्ट

» स्वराज इंडिया ब्यूरो चीफ

कानपुर। 1500 करोड़ से ज्यादा ठगी करने वाला इंटरनेशनल ठग रवींद्र नाथ सोनी से राज खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। ठगी की रकम से तैयार प्रॉपर्टी का पता लगाने रिमांड के दूसरे दिन एसआईटी उसे लेकर देहरादून रवाना हुई है। जहां सोनी की कुंडली खंगालने का प्लान है। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस को उसकी जालसाजी भी सामने आई। महाठग ने अलग-अलग नाम से तीन पासपोर्ट बनवाए हैं। कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़ ही नहीं कई शहरों से उसकी आईडी बनी है। एक आईडी में आरएन सोनी तो दूसरी में रविंद्र नाथ सोनी लिखा है। उसके पासपोर्ट भी अलग-अलग हैं। जिससे वह विभिन्न देशों में भ्रमण कर ठगी करता है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि रवींद्र ने ठगी की रकम देहरादून व एनसीआर समेत अनेकों स्थान पर निवेश किया है। संपत्ति की जानकारी के लिए एसआईटी की टेक्निकल टीम रवींद्र से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। एसआईटी सूत्रों की माने तो रवींद्र ने रकम जिन खातों में भेजे इसकी जानकारी वह नहीं दे रहा है। टेक्निकल टीम पता लगाने के लिए साइबर स्पेशलिस्ट की मदद ले रही है। एसआईटी की माने तो गुरमीत के अलावा उसके गैंग में नाम तो बहुत हैं, लेकिन वह मुंह नहीं खोल रहा है। पूछताछ में रवींद्र ने पुलिस को बताया कि जब उसे जानकारी हुई कि दुबई पुलिस उसे पकड़ने वाली है तो मार्च 2024 को वह भारत आया। रवींद्र नाथ सोनी ने ब्याज का लालच देकर लोगों से ठगी की है। कोतवाली में उसके खिलाफ अब तक पांच रिपोर्ट हो चुकी हैं। जिनकी जांच चल रही है। उसके खिलाफ पहली रिपोर्ट 42.29 लाख रुपये की ठगी की हुई। उसकी कड़ियां खंगालने पर ठगी के मामले खुले। एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया कि रवींद्र दुबई से ओमान के रास्ते भारत आया और दिल्ली में कुछ दिन रहने के बाद देहरादून में था। उसकी संपत्तियां गुरुग्राम, नोएडा, मेरठ, दिल्ली में हैं। रियल स्टेट में भी रकम लगाने की जानकारी है।

शोभन सरकार की तपोस्थली में 13 से शुरू होगा गुरुदेव महोत्सव

» श्रीरामचरित मानस पाठ से होगी शुरुआत, 18-19 को रामलीला का मंचन

» स्वामी रघुनंदन दास की स्मृति में स्वास्थ्य कैंप और हवन-यज्ञ भी होंगे

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। बाघपुर क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध शोभन मंदिर के पास गौरी कुंड आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गौरी महापूजा एवं गुरुदेव महोत्सव का भव्य आयोजन शनिवार से शुरू होने जा रहा है। यह धार्मिक महोत्सव 19 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ 13 दिसंबर को रामचरित मानस अखंड पाठ के साथ होगा। कार्यक्रम के दौरान 18 और 19 दिसंबर को दिन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की बाल लीलाओं का मंचन उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाएगा।

लगाया जा रहा है बड़ा पंडाल

यह आयोजन शोभन स्थित 1008 स्वामी रघुनंदन दास महाराज की तपोस्थली पर उनकी स्मृति में कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। ब्रह्मलीन स्वामी विरक्तानंद महाराज उर्फ शोभन सरकार ने ही

अपने गुरुदेव की स्मृति में गौरी कुंड धाम में इस महोत्सव की शुरुआत की थी। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद आयोजन की परंपरा उनके शिष्य और आश्रम के सर्वराकार स्वामी हरि शरणम पांडेय आगे बढ़ा रहे हैं। पवन तनय आश्रम के संत बाबा गोपालानंद और शोभन मंदिर के महंत पूज्यपाद हरि शरण पांडेय ने बताया कि महोत्सव में प्रतिदिन पूजन, दर्शन, प्रसाद वितरण, हवन-यज्ञ संपन्न होंगे। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जाएंगे। आश्रम में भक्तों की आमद को देखते हुए तैयारियाँ बड़े स्तर पर जारी हैं।

अनुमति के बिना काटे नीम के चार पेड़

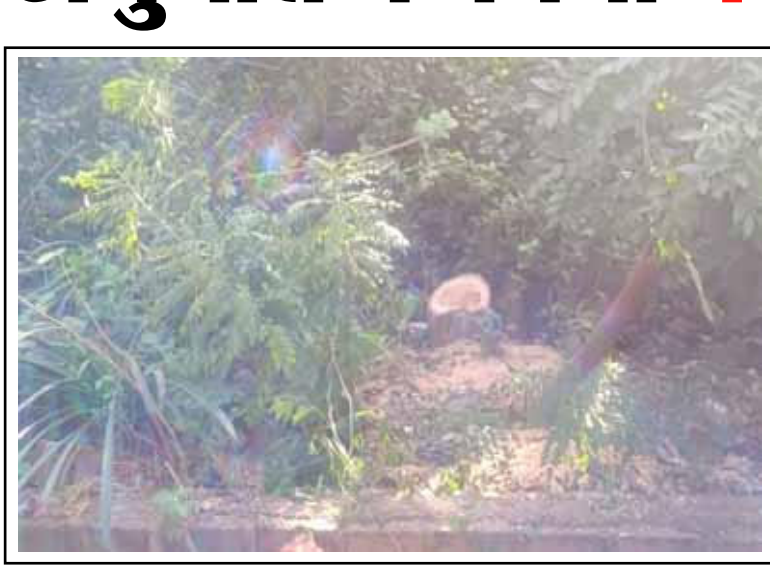

» रेंजर ने कहा, वन अधिनियम के तहत जुर्माना की कार्रवाई की जा रही

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। महाविद्यालय के अंदर खड़े हरे नीम के चार पेड़ों को काट गिराया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने नापतौल कर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है।

बुधवार को राजपुर ब्लॉक क्षेत्र के बुधौली गांव के सडक़ किनारे स्थित राम औतार

महाविद्यालय के अंदर खड़े हरे नीम के चार पेड़ों को वन माफियाओं ने काट गिराया। जिसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई।

सूचना पर पहुंचे वन रक्षक इंद्रेश कुमार मौके पर पहुंचकर काटे गए चार हरे नीम के पेड़ों की नाफ तौल के बाद रिपोर्ट रेंज ऑफिस भोगनीपुर दी गई है। वहीं भोगनीपुर रेंजर स्वामीदीन चौधरी ने बताया कि वन अधिनियम के तहत जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। शेष पेड़ों की कटान पर रोक लगाई गई है।

छापा मारकर 11 जुआरियों को पकड़ा

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाल अमरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्र के मांचा रैगवां गांव समीप भट्टे के समीप कुछ लोग जुआ खेल रहे है।

सूचना मिलते उन्होंने पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचकर 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गये जुआरियों ने अपना नाम राहुल, रिंकू निवासी बिदखुरी, कल्यान निवासी परहेशपुर, मोहित, रवि, अमित पाल, बलराम गुप्ता, बृजेश कुमार, निवासी पुखरायां, अंकित कुमार, जतवेंद्र निवासी मांचा व रविन्द्र निवासी कल्ला, बताया है। पुलिस ने मौके से एक लाख, सत्ताईस हजार, तीन सौ पच्यासी रुपये व पांच मोटरसाइकिल भी बरामद की।

शादी के एक हफ्ते बाद नवविवाहिता लापता, रिपोर्ट दर्ज

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता शादी के एक सप्ताह बाद रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। उसकी शादी बीते 2 दिसंबर को बिठूर निवासी योगेश से हुई थी। मीना नामक महिला ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे संध्या अपनी बुआ के साथ बाजार पहुंची।बाजार में बुआ शिवानी ग्रामीण बैंक से पैसे निकालने चली गईं और संध्या कपड़े खरीदने की बात कहकर वहां से चली गई।

काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब संध्या वापस नहीं लौटी तो शिवानी ने उसकी तलाश शुरू की। संध्या के मोबाइल फोन पर संपर्क करने पर फोन बंद मिला।

परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं सुराग नहीं लगा। जिसके बाद शिवली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। नवविवाहिता की तलाश की जा रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

रोटावेटर में फंसकर युवक की मौत, परिवार में हाहाकार

काशीपुर ग्रामसभा के सलेमपुर गांव की घटना, पुलिस जांच में जुटी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र के काशीपुर ग्रामसभा के सलेमपुर गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। खेत में काम करते समय रोटावेटर में फंसकर युवक रामगोपाल गौतम की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 8 बजे के आस पास ट्रैक्टर ड्राइवर बीरेंद्र यादव, बच्चा यादव और मृतक रामगोपाल गौतम खेत में रोटावेटर चलाने पहुंचे थे।मृतक ट्रैक्टर से उतरकर खेत में टहल रहे थे। इसी बीच उन्होंने रोटावेटर पर चढने का प्रयास किया, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वे सीधे रोटावेटर में जा गिरे।

ड्राइवर जब तक ट्रैक्टर रोकता, तब तक रोटावेटर ने उन्हें बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर है। थाना प्रभारी रूरा ने बताया कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।

घर में घुसकर महिला से मारपीट,जान से मारने की धमकी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बिरहुन गांव में दबंगों ने एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की। आरोपियों ने महिला को जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता शीला देवी ने पुलिस को बताया कि बुधवार को सुबह वह अपने घर पर अकेली थी ।

आरोप है कि इसी दौरान मोहल्ले के मोहित,शोभित,राजेंद्र और दो अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आए।उन्होंने उसे जातिसूचक गालियां देते हुए घर में तोड़फोड़ की और उससे मारपीट की। जब उसने शोर मचाया तो पड़ोसी पहुंच गए।

इस दौरान आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।शीला देवी ने पुलिस को बताया कि उनका परिवार अत्यंत गरीब है।पीड़िता ने बताया कि घर के बगल में खड़ी छोटी सी दीवाल को भी उनकी महिलाओं ने गिरा दिया। जिसका वीडियो भी उसके पास मौजूद है।प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

जनपद में 13 दिसम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

जन-जागरूकता के लिए जिला जज ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक लोगों को इसके लाभों से अवगत कराने के उद्देश्य से गुरुवार को जनपद कानपुर देहात के न्यायालय परिसर से जन जागरूकता वाहन रैली को जिला जज रवीन्द्र सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिला जज रविन्द्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों—जैसे समझौता, योग्य दीवानी वाद, आपराधिक चालान, बैंक रिकवरी, बिजली बिल, पानी बिल, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना, वाहन चालान, दावा वाद आदि का त्वरित एवं तो सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जाता है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है तथा न्यायालय शुल्क में भी छूट दी जाती है।

लोक अदालत गरीबों की अदालत है। जहां कमजोर तबके के लोगों को भी बड़ी राहत मिलती है। जन जागरूकता वाहन रैली का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि, प्रक्रियाओं तथा इसके लाभों की जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे अधिक संख्या में अपने वादों का निस्तारण करा सकें। इस दौरान न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और जनसामान्य से अपील करते हुए कहा गया कि वे 13 दिसंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर अपने लंबित मामलों का समाधान प्राथमिकता से कराएं। इस मौके पर अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हिमांशु कुमार सिंह, नोडल अधिकारी रजत सिंह, शैलेंद्र कुमार निगम, पूनम, रणविजय सिंह सहित न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता आदि जन उपस्थित रहे।

यह है गांव में सड़क का हाल

प्रधान के गांव में ही टूटी सड़के और टूटी नालियों से होता जलभराव

खेड़ा कुर्सी ग्राम पंचायत में मजरों का बुरा हाल

ग्राम प्रधान के दावों की खुली पोल, विकास कार्यों में पीछे रहा खेड़ा कुर्सी गांव

कानपुर देहात। गांव में विकास के नाम पर भले ही करोड़ों रुपए खर्च हो गए लेकिन रसूलाबाद विकास खण्ड के खेड़ा कुर्सी ग्राम पंचायत के मजरों का हाल आज भी खराब है। माजरा गंगादीन निवादा गांव में सडक़ों की दुर्दशा से ग्रामीण परेशान हैं। किसी भी गली में सही रोड न बने होने के चलते मामूली सी बारिश में भारी जलभराव हो जाता है। लोगों का आवागमन भी बंद हो जाता है। कई बार कहने के बाद भी ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की समस्या को नहीं समझा। इसके चलते ग्रामीण परेशान हैं और वोट की चोट देने को तैयार हैं।

जनपद की रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर दिशा में कानपुर जनपद की सीमा से लगे खेड़ा कुर्सी ग्राम पंचायत का बुरा हाल है। खेड़ा कुर्सी का मजरा गंगादीन निवादा निवासी राकेश कुमार मिश्रा, रामसहाय मिश्रा, रामकृष्ण,माया देवी, विमल,पुजारी इत्यादि लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा मजरे के साथ सौतेला व्यवहार किया गयाम गंगा दीन निवादा एक पुराना गांव है। जहां पर बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के लोग निवास करते हैं लेकिन गांव के साथ भेदभाव हुआ। विकास कार्यों के मामले में गांव में कोई कार्य नहीं हुआ। ग्राम में पंचायत सचिवालय तो बन गया लेकिन गांव की सडक़ों की तस्वीर नहीं बदली। गांव को जाने वाले रास्तों पर बड़े-बड़े बबूल के पेड़ खड़े हैं और सडक़ों पर घास जम रही है लेकिन जिम्मेदारों द्वारा न तो साफ सफाई कराई गई और न ही पेड़ों की छटाई हुई। यहां तक 3 वर्ष पहले जहां खड़ंजा ईंट बिछाई जानी थी वहां पड़ंजा ईंट बिछवाकर महज औपचारिकता पूरी कर ली गई। उस रोड पर भी अब गड्ढे हैं और एजिंग भी टूट गई है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कमल नारायण ने बताया कि गांव में एक आरसीसी सडक़ व एक इंटरलॉक अभी बनवाई है। जहां पर सडक़े खराब है। प्रस्ताव देकर जल्द ही सही करवाने का काम करेंगे।

बस्तर की रामायणकालीन औषधियां सरयू तट पर महकेंगी

दंडकारण्य की जीवनरक्षक जड़ी-बूटियां अब अयोध्या के औषधि पार्क में सजेंगी

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।रामनगरी अयोध्या अब बस्तर की अमूल्य वन औषधियों की सुगंध से महकेगी। सरयू तट पर विकसित किए जा रहे रामायण कालीन वन औषधि पार्क में बस्तर के जंगलों में मिलने वाली दुर्लभ और जीवनरक्षक जड़ी-बूटियों को लगाने की तैयारी तेजी से चल रही है। प्राकृतिक संपदा और उपचारात्मक गुणों के लिए प्रसिद्ध बस्तर की ये औषधियां सदियों से वहां के वैद्यों द्वारा संरक्षित की जाती रही हैं, और अब अयोध्या में इनका नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।

प्रभु श्रीराम के वनवास काल में दंडकारण्य जिसका बड़ा भूभाग बस्तर में है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक प्रभु श्रीराम की यात्रा पर पिछले सत्तर वर्षों से शोध कर रही श्रीराम शोध संस्थान, नई दिल्ली ने प्रमाणिक स्थलों और मार्गों के अध्ययन के बाद बस्तर को राम वनगमन पथ का सबसे महत्वपूर्ण खंड माना है। इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जुड़ाव के आधार पर बस्तर की औषधियां अयोध्या के सरयू तट पर नई पहचान बनाने जा रही हैं।

अयोध्या के औषधि पार्क में जिन पौधों को लगाया जाएगा, उनमें अमर कंद, हनुमान बल, कालमेघ, राम तुलसी, शतावरी, चिरायता, मंडुक पर्णी, सीता अशोक, काली निर्गुंडी, नीलकंठ, दशमूल, काली हल्दी, पद्म गिलोय, पीपली, भृंगराज, पिपला जड़ी जैसी दुर्लभ वन औषधियां प्रमुख हैं। इन पौधों को युद्धस्तर पर श्रीराम शोध संस्थान

के बस्तर निवासी कार्यकारिणी सदस्य विजय भारत द्वारा पांच नर्सरियों में तैयार कराया जा रहा है। इसके साथ ही बस्तर के कांकेर से कोन्टा के इन्जरम तक करीब 200 किलोमीटर लंबे राम पथ गमन मार्ग के दोनों ओर मौलश्री, नीम, चंदन, सीता अशोक, रामफल, सीताफल जैसे वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे मार्ग पर चलने वालों को राम वनवास की याद ताजा होगी।

भदोही में सनसनीखेज वारदात

एक दिन में दो कार्रवाई से बौखलाया युवक

कार से कुचलकर शिकायतकर्ता को मार डाला

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

भदोही। भदोही कोतवाली के घसकरी गांव निवासी कमलाकांत दुबे (70) की बुधवार की देर रात कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना को गांव के प्रधान मनीष यादव के भतीजे सुजीत ने अंजाम दिया। कमलाकांत दुकान बंद कर रहे थे। इस बीच सुजीत ने अपना वाहन उनकी दुकान की ओर घुमाते हुए उन्हें शटर व वाहन के बीच दबा दिया। बुधवार को ही प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज होने के साथ सुजीत के पिता मेहीलाल को पुलिस ने 151 में गिरफ्तार किया था। कमलाकांत दुबे ने प्रधान के भ्रष्टाचार और उनके बड़े भाई पर धमकी देने का आरोप लगाया था।

क्या है पूरा मामला

भदोही कोतवाली के घसकरी गांव निवासी कमलाकांत दुबे गांव में ही क्लिनिक चलाते थे। वे गांव में प्रधान मनीष यादव के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी। मामले में जांच के बाद भ्रष्टाचार की शिकायत सही मिली। बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट ने प्रधान के वित्तीय अधिकार को सीज कर दिया। वहीं कमलाकांत की शिकायत पर ही पुलिस ने प्रधान

के बड़े भाई मेहीलाल को बुधवार को ही 151 में चालान कर गिरफ्तार किया।

बताया जा रहा है कि एक ही दिन दो कार्रवाई होने से प्रधान का भतीजा सुजीत आक्रोश से भरा हुआ था। बुधवार की रात कमलाकांत अपनी क्लिनिक बंद कर रहे थे। वे शटर गिराने के बाद जैसे ही ताला लगाने के लिए झुके, इस बीच प्रधान का भतीजा सुजीत अपनी वाहन से उन्हें शटर व वाहन के बीच कुचलकर कार बैक कर भाग गया। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

आनन- फानन कमलाकांत को अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने प्रधान को हिरासत में ले लिया।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मृतक ने प्रधान व उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

जिसमें प्रधान द्वारा गांव में की गई वित्तीय गड़बड़ी और उसके बड़े भाई द्वारा दी जा रही धमकी की शिकायत की थी।

प्रधान का भाई 151 में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद प्रधान के भतीजे ने वाहन से दबाकर कमलाकांत की हत्या कर दी।

पुलिस प्रधान व जेल में बंद उसके भाई से पूछताछ कर रही है।

स्थानांतरण से शुरू हुआ विवाद, निलंबित सीएमएस की 'मनमानी रिपोर्ट' पर कार्रवाई

» निलंबन अवधि में की गई उनकी जांच को शासन ने स्वयं अवैध और असंज्ञेय माना-डॉ0 अजय गुप्ता

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या के शांत प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों होम्योपैथी विभाग को लेकर ऐसा बवंडर उठ चुका है कि शासन की 'पारदर्शिता' पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। एक ओर शासन डॉ. अजय कुमार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाकर उन्हें सोनभद्र सम्बद्ध करता है, वहीं दूसरी ओर जिस रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई वही रिपोर्ट देने वाली अधिकारी डॉ. संगीता भाटिया खुद निलंबित थीं, और बिना किसी सक्षम आदेश के 'स्वत- संज्ञान' लेकर जांच कर रही थीं। विवाद केवल आदेश तक सीमित नहीं बल्कि इसके पीछे की असली चिंगारी उस दिन भड़की जब निलंबित सीएमएस कोर्ट का आदेश लेकर कार्यालय पहुंचीं और कार्यालय पर ताला लटकता मिला। बस, यहीं से शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप, कुर्सी पर कब्जा, और वह पूरा प्रकरण जिसने विभाग को दो खेमों में बांट दिया।

बता दे कि 30 नवंबर 2024 की घटना पूरे प्रकरण का केंद्रबिंदु बनी। निलंबन पर चल रहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होम्योपैथी डॉ. संगीता भाटिया हाईकोर्ट से राहत आदेश लेकर अपने

अयोध्या होम्योपैथी विभाग में घमासान

कार्यालय पहुंचीं। लेकिन उन्हें वहां मिला—लगा हुआ ताला। ताला देखकर भड़कीं डॉ. भाटिया दूसरे तल पर स्थित जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉ. अजय कुमार के कक्ष में पहुंचीं और सीधे उनकी कुर्सी पर बैठ गईं। आरोप लगाया कि फ़बिना आदेश के ऑफिस सील कर दिया गया। शासन की अवहेलना की जा रही है। डॉ. अजय का जवाब था शासन से बहाली का कोई आदेश नहीं मिला था। निलंबित अधिकारी निजी व्यक्ति से कार्यालय चलवा रही थीं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ताला लगा था। यहीं से विवाद ने राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यक्तिगत रंग लेना शुरू कर दिया।

इसी में अवधेश तिवारी नामक व्यक्ति ने 26 नवंबर 2024 को शिकायत दी—कि डॉ. अजय होम्योपैथी औषधियों की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं। यह शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (डॉ. संगीता भाटिया) को भेजी गई। इसके बाद बिना किसी सक्षम आदेश के निलंबन की स्थिति में होने के बावजूद उन्होंने स्वयं जांच अधिकारी बनकर डॉ. अजय पर लगे आरोपों की जांच कर रिपोर्ट शासन को भेज दी। शासन ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर डॉ. अजय के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी। शासन के अपने दस्तावेज़ कहते हैं कि डॉ. संगीता भाटिया 23 अक्टूबर 2024 से निलंबित थीं।उन्हें जांच का आदेश किसी सक्षम अधिकारी ने नहीं दिया था। वह अपने पद पर उस समय पदेन कार्यरत ही नहीं थीं। इसलिए उनकी भेजी जांच संज्ञान

निलंबित चल रही सीएमएस डॉ0 संगीता भाटिया

योग्य नहीं है। फिर भी, उसी रिपोर्ट पर डॉ. अजय का स्थानांतरण कर दिया गया।

डॉ. अजय को आदेश जारी होते ही सोनभद्र से सम्बद्ध कर दिया गया। आरोप था कि 50प्रतिशत तक अधिक भुगतान,कमीशन लेने का संदेह, टेंडर/कोटेशन में अनियमितता। गैर-अनुमोदित दवा खरीद,बिना मांगपत्र के एसी की आपूर्ति और ओपीडी कम करना। हालांकि भीतरखाने की फुसफुसाहट कुछ और कहती है। अयोध्या में लंबे समय से दो गुट भिड़े हुए हैं। स्थानांतरण इसी का परिणाम है।

ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिखा यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं, 'कुर्सी युद्ध' भी है। कुर्सी पर बैठने से लेकर ताला लगाने तक इस विवाद ने होम्योपैथी विभाग को प्रशासनिक साख का आइना बना दिया है। शासन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि निलंबित अधिकारी

मेरे साथ अन्याय हो रहा

डॉ. अजय कुमार का आरोप स्पष्टीकरण है कि मेरे खिलाफ जिस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है, वह एक निलंबित अधिकारी की है। डॉ. संगीता भाटिया को जांच का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। निलंबन अवधि में की गई उनकी जांच को शासन ने स्वयं अवैध और असंज्ञेय माना है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यह शासन की पारदर्शिता और प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। मैंने 11.अप्रैल.2025 को पूर्ण बिंदुवार स्पष्टीकरण शासन को दे दिया है।

की विवादित रिपोर्ट पर ही कार्रवाई क्यों? क्या यह सिर्फ कार्रवाई थी या फिर किसी गुट की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश?

..तो क्या अयोध्या में एसआईआर से भाजपा को लगेगा झटका

» रामनगरी में मतदाता सूची की 'सफाई' से बदला राजनीतिक गणित

» एक लाख से अधिक मतदाता घटेंगे, अयोध्या सीट से ही बड़ा झटका

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या ।राममंदिर के भव्य लोकार्पण के बाद भाजपा को जिस रामनगरी से अक्षय राजनीतिक ऊर्जा मिलने की उम्मीद थी, उसी अयोध्या में इस बार एसआईआर (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) ने पूरी गणना उलट-पलट कर दी है। अब तक विपक्ष एसआईआर को लेकर पूरे देश में अन्याय का अलाप गाता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में इसकी तस्वीर बिल्कुल उलटी दिख रही है यहां इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी, सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा के अंदरूनी खेमों में नफा-नुकसान की खुली चर्चा शुरू हो चुकी है। बीएलओ के घर-घर सर्वे के बाद जो प्रारंभिक तस्वीर सामने आई है, उसने भाजपा रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है।

बता दे कि अकेले अयोध्या विधानसभा से 1,17,306 मतदाता घट रहे हैं—जो कुल मतदाताओं का लगभग 28.90 प्रतिशत है। पूरा जनपद देखें तो कुल 3.45 लाख मतदाता सूची से बाहर हो रहे हैं। राजनीतिक सूत्र बारीकी से बताते हैं कि बाहरी जिलों से आकर अयोध्या में बसे नए मतदाता—लगभग एक लाख से अधिक—भाजपा के मुख्य समर्थन आधार रहे हैं। अनुमान है कि इन मतदाताओं में 80 प्रतिशत भाजपाई झुकाव वाले हैं। ऐसे में यह

जिले की पाँचों विधानसभा सीटों में भारी कटौती

विधानसभा सीट	घटे मतदाता
अयोध्या-	1,17,306
गोसाईंगंज-	73,106
बीकापुर-	65,846
रुदौली	-57,000 (लगभग)
मिल्कीपुर- (आरक्षित)	41,262 (सबसे कम)

'महासफाई' भाजपा के लिए किसी भस्मासुर से कम साबित नहीं हो रही। कोरोना काल में जिस तरह लोग महानगरों से गांव लौटे थे, उसी तर्ज पर एसआईआर के दौरान अयोध्या के नए मतदाताओं में गांव की संपत्ति और पटीदार वर्चस्व का डर दिखाई देने लगा। बहुत से लोग अपने मूल गांव के वोट बचाने के लिए अयोध्या शहर से नाम हटाने लगे। शहरी कॉलोनियों में रहने वाले हजारों नए परिवारों ने भी दोहरे मतदाता होने से बचने के लिए शिफ्टिंग कर दी।

राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह प्रक्रिया भाजपा के शहरी वोट बैंक पर सबसे बड़ा वार है। क्यों 'रामनगरी' में ही भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान? अयोध्या विधानसभा जहां राममंदिर स्थित है पिछले दशक में बाहर से आए मतदाताओं का नया किला बन चुकी थी। नई कालोनियां,

तीर्थ पर्यटन, कारोबार और धार्मिक प्रतिष्ठानज् सब मिलकर अयोध्या को भाजपा का सुरक्षित वोट-हब बनाते गए। लेकिन एसआईआर ने यह किला हिला दिया ।सरकारी आंकड़े बताते हैं 46,000 मतदाता सर्वे में घर पर नहीं मिले।13,388 मृतक निकले। 42,471 स्थानांतरित मतदाता मिले मंदिरों की चेला-प्रणाली वाले हज़ारों वोटों में सत्यापन संभव नहीं हुआ। इन सबने मिलकर अयोध्या की मतदाता संख्या को एक झटके में एक चौथाई कम कर दिया। एक वरिष्ठ स्थानीय भाजपा नेता ने भी कहा कुछ बुलवाइए मत साहब ये बचे वोटर तो इतने वर्षों से गलती से सूची में चले आ रहे थे। अब अपना-अपना जिला पकड़ रहे हैं!

नशीले कोडीन कफ सिरप मामले में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता

दो आरोपी सगे भाई अभिषेक और शुभम लखनऊ में अरेस्ट

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने कोडीन युक्त सिरप का अवैध भंडारण करने में दो आरोपियों सगे भाई अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को लखनऊ में गिरफ्तार किया। दोनों सहारनपुर के रहने वाले है। कोडीन युक्त सिरप प्रकरण की जांच में लगी एसटीएफ और एफएसडीए ने अभी तक कई खुलासे किए हैं।

वहीं सिरप प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी कई बिन्दुओं पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। एसआईटी जांच में यह भी देखेगी कि पिछले साल जांच के बाद दर्ज एफआईआर में पूर्व सांसद का करीबी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा का नाम विवेचना में सामने आ चुका था, फिर भी इसे दबाए क्यों रखा गया। उसे बचाने में लगे रहे पुलिस कर्मियों की भूमिका का भी पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही फर्जी फर्म और फर्जी ई-बिल से कितने करोड़ रुपये की तस्करी की गई, इसके लिए जीएसटी विभाग से पूरा ब्योरा ले लिया गया है। शासन ने इस प्रकरण के तूल पकड़ने पर आईजी एल. कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उसने सबसे पहले अब तक दर्ज एफआईआर का ब्योरा लेने के साथ ही जीएसटी विभाग से उन फर्मों की जानकारी ली है जिनके जरिए वाराणसी से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक सिरप की सप्लाई की गई।

बर्खास्त सिपाही के मददगार पुलिसकर्मियों पर भी नजर

एसआईटी अपनी जांच में यह भी पता करेगी कि आलोक सिंह, अमित टाटा का नाम गाजियाबाद, सोनभद्र और लखनऊ में दर्ज एफआईआर की विवेचना में नाम सामने आने के बाद उन्हें बचाने की कोशिश किसकी शह पर की जाती रही। इसमें आलोक के मददगार पुलिस कर्मियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही आलोक सिंह द्वारा बनाई गई दो फर्मों मां शारदा व एक अन्य के लेन-देन का भी ब्योरा लिया गया है। इसके अलावा एसआईटी ने एफआईआर से सम्बन्धित जिलों की पुलिस, एसटीएफ की अब तक की कार्रवाई की पूरी जानकारी लेने के साथ ही ईडी से भी सम्पर्क किया है। ईडी भी इस मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) ने भी कफ सिरप प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। नारकोटिक्स ब्यूरो के लखनऊ कार्यालय ने कई फार्मा कम्पनियों को आवंटित किए जाने वाले कोडीन का ब्योरा मांगा है। कोडीन युक्त सिरप की तस्करी को लेकर ही इस समय हड़कम्प मचा हुआ है। नारकोटिक्स ब्यूरो के अफसरों के मुताबिक नशीले कफ सिरप की सप्लाई में कई गिरोह लगे हुए है। इनको ये सप्लाई ग्वालियर से की जा रही थी। इस पर ही ब्यूरो की टीम ने ग्वालियर से इन फार्मा कम्पनियों का ब्योरा मंगवाया है। छह महीने प हले नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो ने अमीनाबाद में छापा मार कर नशे में इस्तेमाल होने वाली लाखों टेबलेट के साथ कोडीन युक्त सिरप की बोतलें बरामद की थी।

एफएसडीए की जांच में 12 चेहरे हुए उजागर

वहीं दूसरी ओर एफएसडीए की जांच में सिंडिकेट में शामिल 12 नाम सामने आए हैं। इनमें सहारनपुर का विभोर राणा, विशाल राणा, विशाल उपाध्याय, गाजियाबाद का सौरभ त्यागी, शादाब, अभिषेक शर्मा, पप्पन यादव, वाराणसी का भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, आकाश पाठक, लखनऊ का मनोहर जायसवाल और कानपुर का विनोद अग्रवाल शामिल है।

लोकतंत्र की शुचिता के लिए एसआईआर जरूरी: ब्रजेश पाठक

लखीमपुर खीरी, स्वराज इंडिया ब्यूरो। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक बृहस्पतिवार को लखीमपुर खीरी के दौरे पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन मैदान पर उतरने के बाद दोपहर करीब 12:15 बजे वह भारतीय जनता पार्टी के देवकली रोड स्थित जिला कार्यालय पर पहुंचे। यहां पार्टी के सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों समेत संगठन के लोगों के साथ एसआईआर की समीक्षा बैठक की। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि जैसे मन की शुद्धता के लिए योग आवश्यक है, वैसे ही लोकतंत्र की शुचिता के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है।

उपमुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा मुखिया की अपनी संभावित हार को नजदीक आते देखकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ। वहां प्रचंड बहुत के साथ एनडीए की सरकार आई। लगभग 65 लाख ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया, जो अवैध मतदाता थे। चुनाव आयोग को भाजपा के कार्यकर्ता बीएलओ के माध्यम से मदद कर ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर करवा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो रही है।

बीडीओ प्रतीमा शाक्य को एक लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

अंतिम किस्त जारी करने के लिए ठेकेदार से मांगे थे रुपए

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस बड़ी कार्रवाई में झांसी से आई विजिलेंस टीम ने कदौरा ब्लॉक की महिला खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रतीमा शाक्य को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गोपनीय जांच के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिसमें 14 अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम शामिल रही।

दरअसल, शिकायतकर्ता ने झांसी विजिलेंस टीम को दी लिखित शिकायत में बताया था कि उसकी फर्म विधान सिद्धार्थ कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर्स द्वारा जूनियर स्कूल सड़क (इंटरलॉकिंग रोड) का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया था और कुल भुगतान 878262 रुपये के बिल की अंतिम किश्त रोकी जा रही थी।

आरोप है कि बीडीओ प्रतीमा शाक्य द्वारा अंतिम किश्त जारी करने के बदले में 100000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया किया कि वह रिश्वत नहीं देना चाहता, बल्कि महिला अधिकारी को रंगेहाथ पकड़वाना चाहता है। वहीं, ठेकेदार की शिकायत के अनुसार टीम ने शिकायत की पुष्टि के लिए गोपनीय जांच शुरू की। सभी तथ्यों के सही पाए जाने के बाद 10 दिसंबर को टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की। जैसे ही शिकायतकर्ता से तय की गई रकम 100000 रुपये बीडीओ ने स्वीकार की, टीम ने मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मौके से रकम बरामद कर ली गई। इसके बाद आरोपी अधिकारी को पुलिस हिरासत में लेकर कदौरा थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया।

विजिलेंस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद टीम ने अपनी गोपनीय जांच शुरू की इसके बाद सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

एक दिन में दो कार्रवाई से बौखलाया युवक, शिकायतकर्ता को कुचलकर मार डाला

भदोही, स्वराज इंडिया ब्यूरो। भदोही कोतवाली के घसकरी गांव निवासी कमलाकांत दुबे (70) की बुधवार की देर रात कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना को गांव के प्रधान मनीष यादव के भतीजे सुजीत ने अंजाम दिया। कमलाकांत दुकान बंद कर रहे थे। इस बीच सुजीत ने अपना वाहन उनकी दुकान की ओर घुमाते हुए उन्हें शटर व वाहन के बीच दबा दिया। बुधवार को ही प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज होने के साथ सुजीत के पिता मेहीलाल को पुलिस ने 151 में गिरफ्तार किया था। कमलाकांत दुबे ने प्रधान के भ्रष्टाचार और उनके बड़े भाई पर धमकी देने का आरोप लगाया था।

भदोही कोतवाली के घसकरी गांव निवासी कमलाकांत दुबे गांव में ही क्लिनिक चलाते थे। वे गांव में प्रधान मनीष यादव के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी। मामले में जांच के बाद भ्रष्टाचार की शिकायत सही मिली। बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट ने प्रधान के वित्तीय अधिकार को सीज कर दिया। वहीं कमलाकांत की शिकायत पर ही पुलिस ने प्रधान के बड़े भाई मेहीलाल को बुधवार को ही 151 में चालान कर गिरफ्तार किया।

सेना पर विवादित बयान में आजम खां कोर्ट से बरी

बेटे के साथ रामपुर जेल में है बंद

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

रामपुर। सेना पर विवादित बयान के मामले में आजम खां को कोर्ट से राहत मिल गई है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता को दोषमुक्त करार दिया है। यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया था।

आरोप था कि आजम खां सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सेना के जवानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। पुलिस ने जांच पूरी कर आजम खां के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चला। इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां को बरी कर दिया है।

13 मामलों में आ चुका है फैसला, सात में हुई सजा

सपा नेता आजम खां पर 84 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 13 मामलों में कोर्ट फैसला सुना चुका है। इनमें से सात मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है, जबकि शेष मामलों में वह बरी हो चुके हैं। दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सात साल की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने दोनों पिता-पुत्र को दो पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में भी सजा दी जा चुकी है। फिलहाल दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।